

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेल फिलिप्पा

भारतीय बस्ती

बस्ती 1 सितम्बर 2024 रविवार

सम्पादकीय

प्रदूषण और नियंत्रण

यह खबर उत्साहवर्धक है कि भारत में सूक्ष्म कणों से पैदा होने वाले जानलेवा प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन अभी जीवन प्रत्याशा घटाने वाले प्रदूषण को लेकर जारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की हालिया वार्षिक रिपोर्ट 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' बताती है कि भारत में साल 2021 की तुलना में 2022 के वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की कमी आई है। हालांकि, यह उपलब्धि मौजूदा हालात में बहुत बड़ी तो नहीं कहा जा सकती है, लेकिन यह बात उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इक्वावन दिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, हम अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन एक विश्वास जगा है कि युद्ध स्तर पर प्रयासों से भयावह प्रदूषण के खिलाफ किसी हद तक जंग जीती भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' में यह भी चेतावनी गयी है कि यदि भारत में डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 के सांद्रता मानक के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी आने की आशंका पैदा हो सकती है। दरअसल, पीएम-2.5 हवा में विद्यमान ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे श्वसनतंत्र पर घातक प्रभाव डालते हैं। उल्लेखनीय है कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित प्रदूषण में आई गिरावट की वजह अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियाँ बतायी गई हैं। हालांकि, हकीकत यह है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये चलायी जा रही कई योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का भी इसमें योगदान रहा है। खासकर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जिन शहरों को शामिल किया गया था, वहां भी पीएम-2.5 सांद्रता में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वच्छ इंधन कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव प्रदूषण नियंत्रण पर नजर आया है। इससे भारत के रिहाइशी इलाकों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का सुझाव भी दिया गया है।

बहरहाल, हमें वर्ष 2022 के उत्साहजनक परिणामों के सामने आने के बाद व्यापक लक्ष्यों के प्रति उदासीन नहीं होना है। यह एक लंबी लड़ाई है और इसमें सरकार व समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। हमें इस अग्र में नहीं रहना चाहिए कि सरकारों के भरोसे ही लगातार गहवते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में हर साल ठंड की दस्तक के बाद पानी जलाने और दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद जो प्रदूषण का बड़ा संकट खड़ा होता है, उसमें हम अपनी जिद व लापरवाही की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम न भूलें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गिनती लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में होती रही है। दरअसल, पीएम-2.5 कणों की सांद्रता बढ़ाने में हमारी लापरवाही की बड़ी भूमिका होती है, जिसमें सड़कों पर बहते वाहनों का दबाव भी शामिल है। जिसके मूल में हमारी लचर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी है। हालांकि, राजधानी समेत कई अन्य राज्यों में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद प्रदूषण में काफी कमी आई है। इस दिशा में हमें दीर्घकालीन नीतियों के बारे में सोचना होगा। हमारी कौशिल्य इकाई कि घनी आबादी के बीच चलायी जा रही औद्योगिक इकाइयों को शहरों से दूर स्थापित किया जाए। हमारे उद्यमियों को भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना चाहिए। नीति-निर्णयताओं को सोचना चाहिए कि प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद दिल्ली आदि शहरों में चलाये जाने वाले ग्रेड्डेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप जैसी व्यवस्था को नियमित रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि बढ़ता प्रदूषण नवजात शिशुओं तथा बच्चों की जीवन प्रत्याशा पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। निरसंदेह, लगातार जहरीली होती हवा से मुक्ति नीति-निर्णयताओं की प्राथमिकता में शामिल होनी चाहिए। ऐसे में हमें पराली की निस्तारण, औद्योगिक कचरे के निपटान तथा कार्बन उत्सर्जन करने वाले इंधन पर रोक लगाने जैसे फौरी उपाय तुरंत करने चाहिए। ऐसे तमाम प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने की जरूरत है जो हमारे जीवन पर संकट पैदा कर रहे हैं।

उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी की रणनीति



-अजय कुमार-

उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को पूरी तरह सक्रिय कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में बड़े झटके का सामना करना पड़ा था, जिससे अब वे उपचुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से लगातार अलग-अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए जीत की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को सभाने और विकास परियोजनाओं के जरिए जनता की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है, ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके।



मिल्लीपुर, कटहरा, मझवां और सीसामऊ जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें से नौ सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुईं, जबकि सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इफ्रान सोलंकी के राजा होने के कारण खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से तीन सीटें जीती थीं, जबकि पांच सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं। शेष दो सीटें पर राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक आंदोलन पार्टी के विधायक काबिज थे।

दरबंदे वाली सीटों पर विजय हासिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने का अक्सर भी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छह सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे, जिससे पार्टी की कितना बहादुर थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती अभियान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने खुद मैदान में उतरकर सियाली माहौल बनाने का मिशन शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू किया। अंबेडकर नगर से इस अभियान की शुरुआत हुई और इसके बाद आयोधा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रोजगार मेलों का आयोजन करके लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हर जिले में पांच हजार से लेकर 17 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाले उन जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में युवाओं को

मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, योगी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने लाम्हाईपरक योजनाओं के प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट्स वितरित किए हैं। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी ने उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी के लिए मजबूत आधार तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

बीजेपी की रणनीति में विकास, रोजगार और संपन्न को मुख्य हथियार बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को युवाओं की बेरोजगारी को लेकर मिली नाराजगी का सामना करना पड़ा था, जो पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण बना। इस ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेलों का आयोजन करके युवाओं को सभाने की कोशिश की है। इन मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी ने अपनी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने हिंदूत्व के एगेंडे को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ताकि विस्फोटक हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में उपचुनाव वाली सीटों के नेताओं के साथ बैठकें की और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने न केवल राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि शासन स्तर पर भी तैयारी की है,

जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। उन्होंने दोनों हिंदी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को भी इस चुनौती अभियान में शामिल किया है, जिनके जिम्मेदारों-दो-दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में बीजेपी के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।

इन उपचुनावों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा की मजबूत सीटें हैं। करल, कुदरकी, कटहरा, मिल्लीपुर और सीसामऊ जैसी सीटें बीजेपी के लिए काल्पनिक माना जा रही है। इसके अलावा, मझवां, मीरपुर और फूलपुर जैसी सीटें भी पार्टी के लिए आसान नहीं हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पूरी तरह से इन सीटों पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती अभियान को निर्भीकता से लेते हुए पूरी ताकत आगे दी है। रोजगार, विकास और संपन्न के माध्यम से बीजेपी की रणनीति को मजबूत किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी की यह मेहनत बीजेपी को उपचुनावों में कितनी सफलता दिला पाती है और पार्टी इस जग को कैसे फलदा करती है।

कश्मीर में बढ़ते आतंक का जिम्मेदार कौन?

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वासे स्थित कारगिल वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान को सबक चेतावनी देते हुए कहा, 'उन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म कर मुहंटाड़ जबवा देंगे।' 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी प्रणामजनी ने सजीव स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 की याद ताजा करवाई। अतिपथ व्यवस्था के बारे में उन्होंने द्वासे में कहा कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सेना को संदेव ही युद्ध के लिए तैयार-बर-तैयार रखना है और यह स्वयंसेना की ओर से किए गए सुधारों की एक मिसाल है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कुछ और मुद्दे भी उजागर किए।



भीतर से खतरा क पाकिस्तान की वर्ष 1947-48 की लड़ाई में हुई शमनका हार का बदला लेने की भावना के साथ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने एक अतिरिक्त कश्मीर (पीओके) के अंदर वर्ष 1965 के शुरू में '4 पुलिस टुकड़ों के अंतर्गत कश्मीर पर 9000 प्रशिक्षण प्राप्त घुसपैठियों को अगस्त के पहले सप्ताह इस्लामा के नारे के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के इलाके कारगिल से लेकर जम्मू के पहाड़ों की ओर पहाड़ियों तक ढेर करके दिया जो अभी भी नियंत्रण में है। परम् से 9 जिलों में वितरित हैं। परम् से लेकर अब तक आतंकियों के साथ युद्ध के दौरान आतंकियों में 18 सुसिखा कर्मचारी अपना बलिदान दे चुके हैं। इनमें से 14 तो जम्मू क्षेत्र में ही शहीद हुए जिनमें 2 कैप्टन, 1 वी.आर.एफ. इंस्पेक्टर तथा कौन जवान शामिल थे। आतंक में आतंकवाद का जन्मदाता तो आयुब खान ही है। जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में 5 पुलिस कर्मियों और एक अध्यापक को देश विदेशी गतिविधियों में शामिल होने के दोष में संविधान की धारा 311 (2) के नीचे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। एम के लिये फिर से पैदा हो जाते हैं नगरे किस तरह यह मांलू नही।

घाटी के अंदर हेरौनीजनक नेद उस समय खुला जब वर्ष 2012 में एक पुलिस कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। सुविधा पूर्ववर्तियों को करीब डेढ़ साल तक जांच करने के उपरांत पता चला कि कुछ पुलिस स्टाफ आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों और सुरक्षाबलों पर निशाना संचार रहे। कश्मीर रेंज के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) शिव मुरारी सहाय के अनुसार जम्मू-कश्मीर के कांस्टेबल अब्दुल रशीद शींगान ने हिजडुल मुजाहिदीन के एक रिहा किए गए आतंकी

के गूढमंत्री मुस्ताक अहमद लोन की हत्या के पीछे एक एच.एच.ओ. तथा एक नृश्री का हाथ था। अब सवाल पैदा यह होता है कि जम्मू-कश्मीर की करीब 140 लाख गिनती वाली पुलिस फोर्स में कितने इस किस्म के अधिकारी होंगे जिनकी तारं आतंकवादियों और कुछ नेताओं के साथ जुड़ी हो सकती है। इसका जवाब तो जम्मू-कश्मीर के प्रशासक ही दे सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वारदातें करने वाले फिर जंगलों व घाटी में ही समा जाते हैं जो कितने बिना किसी स्थानीय मदद के संभव नहीं है। हादसों तो सेना को ही देने पड़ती है।

अराजक राजनीति से अपराध के दलदल में भ्रूलोक



-उमेश चतुर्वेदी-

बंकिम चंद्र की शय्य-श्यामला माला पराध समाज बंगाल एक शक्ति-पूजक समाज है। शरद ऋतु के स्वागत के साथ बंगाल की धरती हर साल मां दुर्गा के स्वागत में विभोर हो जाती है। बंगाल में महिलाओं का सम्मान किस प्रकार की परंपरा का हिस्सा रहा है, इसे समझने के लिए दुर्गा पूजा के विधान को समझना चाहिए। मृतियों को बनाने के लिए सस्से पहले उन वैश्याओं के घर से मिट्टी लाई जाती है, जिन्हें समाज आम तौर पर व्याज्य और नदी मानता है। इसी प्रकार बंगाल की धरती कितनी नरकी-पूजक रही है, यह स्वतंत्र निदान समझ के इतिहास में भी देखने को मिलता है। जो अन्य राज्यों में कम ही मिलता है।

स्वतंत्रता संग्राम में जिन जितनी महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपने ज्ञान व संघर्ष से भारत को आलोकित किया, वे तीनों बंगाल की बेटियाँ थीं। पहली थी अरुणा गांगुली, जिन्होंने बाद में अरुणा आसफ अली का नाम अपनाया। दूसरी थी सुभद्रा नय्यगुप्त, जो सुभद्रा कुलश्री के नाम से प्रसिद्ध हुईं। तीसरी थी रोजमिनी कृष्णध्याय, जिन्होंने बाद में भारत को कौटिली साहयिनी नायक का नाम पाया। बंगाल की माटी ने महिलाओं को बिनता समाज दिया, इसका अर्थ और उदाहरण कमना देवी एडवांथोपथाय हैं। जब भारत के अन्य इलाकों की महिलाएं घृष्ट के पीछे सिर्फ परिवार के काम में व्यस्त थी, तब बंगाल ने अपनी बेटियों को जाजिन समाज और अवसर दिए। बंगाल में सभी महिलाओं के साथ बराबरकी की कल्पना तक नहीं की जाती थी। अब स्थिति बदल गई है। इसका एक उदाहरण हाल ही में शशांगोदिक कर अस्पताल में हुई घटना है।

आजादी से पहले कश्मीर अलग रियासत थी। करीब 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजाओं ने पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लड़ाई लड़ा। उस समय इस रियासत की सीमाएं अफगानिस्तान और चीन से लगती थीं। ऐसे में कश्मीर रणनीतिक तौर पर बेहद अहम था।

इतिहास अहमद उर्फ रशीद के साथ मिश्रकर 18 महीनों में 13 बार जांचक हमले किए जिनमें से एक घातक हमला 11 दिसम्बर 2011 को जम्मू-कश्मीर के कानपुर एच.टी.आई का उपायक भीम अली मोहम्मद सान्गर के ऊपर भी किया गया। आई.टी. सहाय के उस समय के बयान के अनुसार अब्दुल को जब हिरासत में लिया गया तो उस समय वह

सशस्त्र पुलिस के सुरक्षा विंग में उड़ती निभा रहा था। निष्कर्ष में बर्ती होने से पहले उसकी पृष्ठभूमि आतंकी गतिविधियों वाली रही है। उस एक साल नजरबंद किया गया परन्तु अदालत के फैसले के अनुसार वर्ष 2012 में उसे वापस सुरभीमकोट की ओर से सख्त फंसले के बाद सरकार को ही सुचना पड़ा। इससे पहले भी वर्ष 2002 में राज्य

के केंबल वाली नजर क पाकिस्तान को केवल बाद-वार चेतावनी देने के साथ बाद नहीं बनेगी क्योंकि 'लातों के लूट वातों से नहीं मानते।' जबरन इस बात की है कि आतंकियों के मद्देनार और कसूरवार राजनीतिक नेता, प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को बख्शा न जाए। जम्मू-कश्मीर के पुलिस विभाग में सद्योदल करने से ही आतंकियों के सहायक समर्थ होगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री और से अतिथिपथ योजना वा बन रेक वन पैशन (ओ.आर.ओ.पी.) जैसे नुदों के बारे में राजनीतिक करना शोभा नहीं देता।

उल्लेखनीय है कि जब दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध के समय यह महसूस किया कि शहीदों के परिार्यों बल्कि समस्त सैनिक वर्ग के कल्याण के बारे में कोई नीति नहीं है तो उन्होंने 'सिंहों के लिये जीवन' फौजी सैनिकों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। मगर अफसरों की बात है कि 25 वर्ष वीतने के बाद भी यह नीति नहीं बना। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि उसके बारे में जिक्र करते। इसी तरह ओ.आर.ओ.पी. को लागू करने में सरकार की ओर से बार-बार अचूकने डाली गई। आधिकारिक सुरभीमकोट की ओर से सख्त फंसले के बाद सरकार को ही सुचना पड़ा। इन्होंने कुलदीप सिंह काहलौं (रि.टा.)

होता था। युवा वा फिर सत्तारोपी तंत्र का चारण बनाया गया। प्रशासन का यह चारण रूप 16 अगस्त को भी दिखा, जब आरजी की की पीडिता की रिपोर्ट साढ़े प्याह्र बजे रात को दर्ज की गई, जबकि बलात्कार और हत्या पंद्रह अगस्त की रात दो से साढ़े बजे के बीच हो चुकी थी। इसे सुभीम कोर्ट ने भी नोडिस किया और कोलकाता पुलिस को फटककर भी लाया। ममता की अगुआई में कोलकाता में बलात्कार और हत्या के विवेच में बयान दिया गया। यह धरणा पुराण थी, जो सरकार के खिलाफ संपन्न द्वारा ही दिया गया था। ऐसा किनी ही लोलात्तात्रिक समाज में कम से कम अब नहीं देखा गया है। ममता ने प्रशासन को कोई गुणात्मक बदलाव नहीं किया, बल्कि मायापथ जैसी केंडर व्यवस्था को अपना लिया। इससे राज्य में अपराध बढा और पुलिस का इन्वेलव कम हुआ। पुलिस की लाचरगी आरजी कर बलात्कार के विवेच में बयान दिया गया तो कहा जाता है कि 'बंगाल जो आजा सोचता है, वैसी ही सोच भीष्मथ को कायम रखते हुए भ्रूलोक समाज को चाहिए कि वह इस दिशा में भी सचेत हो। उसका गुस्ता एक ऐसे बंगाल के रचना कर, हरन रवींद्र संगीत गुप्तार रहे, बंकिम के गीत गान जाए और नरियां व्यक्तित्व से काम कर सके। जादू विद्वैत खेला होगा, पुष्पेरी दुःखार लोनों के लिए असहयोग हो।

